



अधिकतम : 30°C  
न्यूनतम : 22°C

आबरे छुपावा नहीं, छापवा है

C M Y K

# शाह टाइम्स

मेरठ, शनिवार 12 जुलाई 2025 मेरठ संस्करण: वर्ष 19 अंक 41 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विद्युत खबरों के लिए QR  
कोड स्कैन करें।  
मुफ्त पढ़ें E-paper

C M Y K

C M Y K

C M Y K

C M Y K

C M Y K

C M Y K

C M Y K

C M Y K

C M Y K

C M Y K

C M Y K

www.shahtimesnews.com

shahtimes2015@gmail.com

श्रावण कृष्ण पक्ष 1 विक्रमी सम्बत 2082

16 मुहर्म 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुगादावाद, बोली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



ओडिशा के जंगल- जनीन मित्रों के हवाले कर रहे  
मोदी: खड़गे-शहुल

पैज 2



लॉइंग्स टेस्ट: राहुल व नायर ने भारतीय पारी अंगाली  
खेल टाइम्स



चंद्रपूर बंगला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का पत्र संकारक को  
चेतावनी!



अमेरिकी हमले में भी बच गया  
ईरान का पटमाण कार्यक्रम

पैज 12

शुभांशु शुक्रवार  
14 जुलाई को  
धरती पर लोटेंगे  
टेक्सास। भारतीय  
एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्रवार 14  
जुलाई को धरती पर लौटेंगे।  
अमेरिकी संसद एजेंसी नासा ने  
इसकी जानकारी दी।

एक्सिसओम-4 मिशन के तहत<sup>1</sup>  
शुभांशु सहित चार क्रू सदस्य  
इटरनेशनल स्पेस स्टेशन  
(आईएसएस) पहुंचे थे।

एक्सिसओम-4 मिशन के 25 जून  
को प्रस्तुरिया के कैनेडी स्पेस  
सेंटर से लॉन्च किया गया था।  
इंग्रेजी अंतरिक्ष यान 28 घंटे की  
यात्रा के बाद 26 जून को  
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर<sup>2</sup>  
डॉक किया गया था। हालांकि,  
यह मिशन 14 दिनों का था। अब  
एस्ट्रोनॉट ने वापसी का बाहर  
दर्दी से होगी। इससे पहले 6  
जुलाई को शुभांशु के  
आईएसएस स्टेशन से कछु  
तस्वीरें आई थीं जिसमें  
शुभांशु कपोला मॉड्यूल के  
विंडो से पुथुते देखते नजर आ  
रहे थे। कपोला मॉड्यूल एक  
गुबुद्धुमा अब्जेशन विंडो है,  
जिसमें 7 खिडकियां हैं।

शुभांशु कपोला मॉड्यूल के  
विंडो से पुथुते देखते नजर आ  
रहे हैं। इसके बाद 7 खिडकियां  
गुबुद्धुमा अब्जेशन विंडो हैं।

गुजरात महिसांगर पुल  
हादसा: मृतक संख्या

19 हुई, दो लापता  
अहमतावाद। गुजरात के  
बादवाड जिले में महिसांगर नदी  
पर बने पुराने पुल से पहरे से  
मरने वालों की संख्या बढ़कर  
19 हो गई है। शुभांशु का एक

घायल शाखा की अस्पताल में  
मौत हो गई। दो लाग अपनी भी  
लापता हैं। एनडीआरएफ और  
एस्ट्रोनॉट का सर्वे  
अपरेशन जारी है। बड़ोदरा  
कलंकवर अनिल धर्मेन्द्रिया ने  
कहा कि नीरी भी एक टैक्टैकर  
में सल्मूरिक एसिड पम्प गया।

एसें में पता लाया जा रहा है कि  
उसमें से कोई रिस्पावन न हो। वहीं  
पानी सोडा ऐसे (सोटिम  
कावांनेट) होने के बाद रेस्वू  
टीम होने के बाद और खुली हो  
रही है। हादसे में एक धूपिया  
के तीन लागों की मौत हो गई है।

अमरनाथ यात्रियों की  
सुरक्षा के लिए

अपरेशन शिवांगी शुरू  
नई अमरनाथ यात्रा सुरक्षा

और सुरक्षित यात्रा के लिए  
नागरिक प्रशासन और केंद्रीय  
संस्कृत पुलिस बलों के साथ

मिलकर। अपरेशन शिवा

2025 का शुरू किया है। इस

विशेष अभियान का उद्देश्य

विशेष रूप से अपरेशन सिंदूर

के बाद वायक्स्टान संस्थान  
छाया लाकर अपरेशन सिंदूर  
से खटकर के देखते हुए उत्तरों और

दक्षिणों को बायक्स्टान से खटक

करने पर केंद्र व राज्य

सरकार को नोटिस

बोलेट्रॉनिक। कॉन्टैक्ट हाइकॉर्ट

नें कन्नड़ भाषा की पढ़ाई अनिवार्य

करने पर केंद्र व राज्य

सरकार को नोटिस

बोलेट्रॉनिक। कॉन्टैक्ट हाइकॉर्ट

नें केंद्र सरकार से जवाब मांगा

है। इसके लिए तीन हफ्तों का

समय दिया गया। अदालत ने राज्य

और केंद्र सरकार को नोटिस भी

जारी किए हैं। राज्य की सीबीएसई

कन्नड़ की पढ़ाई सुरक्षा

करने के लिए 2023 में एक जनहित

याचिका दायर हुई थी।

शॉल ओढ़ाने पर समझें उब हो चली: भागवत

## भागवत के नुंह से निकली '75 उब की दलील' को कांग्रेस ने लपका

कांग्रेस बोली: प्रधानमंत्री को भी हो जाना चाहिए दिटायर

नागपुर, वार्ता



■ मोदी और  
भागवत इसी साल  
सितंबर में 75  
साल के हो जाएंगे  
■ संघ प्रमुख के  
बवाने पर सियासी  
घमासान

जयराम रमेश ने एस्ट्रेस पर  
दरमान, पोमोडी 10 जुलाई  
को 5 देशों की विवेसा बायां से  
लौटे हैं। जयराम रमेश ने इसे ही  
उनकी भर वापसी बताया। भागवत  
में 75 साल के बाद भागवत  
का विवेसा किए गए। 2025 को  
को 75 साल के हो जाएंगे।

जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम  
नहीं है। हालांकि, उब कठ सम्भव  
कर सकते हैं। क्योंकि वापसी  
उदाहरण के लिए, दो भी 11

प्रमोटीव भागवत के भीतर एक

दरमान, पीमोडी 10 जुलाई

को भीतर एक नियम है।

उत्तराखण्ड के बाद वर्ष 2025 को  
जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम  
नहीं है। हालांकि, उब कठ सम्भव  
कर सकते हैं। क्योंकि वापसी  
उदाहरण के भीतर एक नियम है।

प्रमोटीव भागवत के भीतर एक

दरमान, पीमोडी 10 जुलाई

को भीतर एक नियम है।

उत्तराखण्ड के बाद वर्ष 2025 को  
जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम है।

उत्तराखण्ड के बाद वर्ष 2025 को  
जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम है।

उत्तराखण्ड के बाद वर्ष 2025 को  
जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम है।

उत्तराखण्ड के बाद वर्ष 2025 को  
जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम है।

उत्तराखण्ड के बाद वर्ष 2025 को  
जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम है।

उत्तराखण्ड के बाद वर्ष 2025 को  
जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम है।

उत्तराखण्ड के बाद वर्ष 2025 को  
जयराम रमेश ने आगे लिया कि  
प्रधानमंत्री भी सासंस्कारिक ल

भागवत के भीतर एक नियम है।

















## भागवत की टिप्पणी

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उम्र को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला, जिससे देश में एक नई वहस छिड़ गई। राम जन्म भूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगल पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मोहन भागवत ने कहा डाला कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनका कहना था कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर शांत और दृढ़ जाने लगे, तो समझाएं कि दूसरों को मोहन देने का समय आ गया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियाँ में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर मोहन भागवत का इशारा किस तरफ है। जैसाकि होता है न्यायाधीशों को सेवानिवृति के बाद केवल छह माह तक ही सकारी आवास के उपयोग की प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट को चार वर्षमान न्यायाधीशों के लिए आवासों की आवश्यकता है।

**इ**स खुलासे से कि न्यायपूर्ति चंद्रचूड़ से सरकारी आवास खाली करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति विद्या क्या देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की जनता में प्रतिष्ठा करने वाली हुई होगी या पिर क्या ऐसा होगा कि चंद्रचूड़ और उनके परिवार के प्रति जनता की सहानुभूति बढ़ गई और चर्चा या आलोचना सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा उठाए गए अधिकृत कदम और सरकार की भूमिका पर कहिए होंगे?

देश भर के अखबारों/टीवी चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित/प्रसारित किया था कि सेवानिवृति के आठ महीने बाद भी चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के आवास पूल में मुख्य न्यायाधीश के लिए निधारित बंगला खाली नहीं किया। न्यायाधीशों को सेवानिवृति के बाद केवल छह माह तक ही सकारी आवास के उपयोग की प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट को चार वर्षमान न्यायाधीशों के लिए आवासों की आवश्यकता है।

चंद्रचूड़ साहब ने अपने स्पष्टीकरण में जिन बातों का खुलासा किया था कि उनके बैटियों गंभीर जोरिक और न्यूरोलोजिकल समस्याओं से जूझ रही हैं। उनके इलाज के लिए आवास में एक विशेष प्रकार के चिकित्सीय सेट-अप की जरूरत पड़ती है। उन्होंने सरकार से किए एवं पर वैकल्पिक आवास उपलब्ध करावाने की प्रार्थना की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

चंद्रचूड़ साहब ने तकालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खना से दिसंबर 2024 में निवेदन किया था कि बर्तमान आवास में 30 अप्रैल तक रहें करने के अनुमति दे दी गई थी। उन्होंने न्यायमूर्ति खना से 28 अप्रैल को पुनः आवेदन किया कि चंद्रचूड़ साहब ने बर्तमान मुख्य न्यायाधीश की जरूरत थी। सामान अब पैकड़ है और ठेकेदार का ओंके मिलते ही शिफ्ट कर रहे हैं।

चंद्रचूड़ साहब के इस कथन के बाद कि जिस आवंटन तक बढ़ा दिया जाए। इस आवेदन का उन्हें कई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक चंद्रचूड़ साहब ने बर्तमान मुख्य न्यायाधीश वीआर गवर्नर के संज्ञान में भी यह बात ला दी थी कि सरकार ने वैकल्पिक आवास आवंटन कर दिया है और आवश्यक मरम्मत के बाद ठेकेदार ने उसे 30 जून तक सौंपें कर वायदा के मार्गदर्शक मंडल एवं भी बनाया गया था। तू तो उम्र में उनके अनुभवों का लाभ पार्टी उठाए सके। उन्हाँने यही न्यायमंत्री के लिए सीमाएं लागू की गई हैं, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में यह नियम कड़वा से लागू किया गया और भाजपा के कई कदावर नेता संविधानिक पदों की जिम्मेदारी से बाहर हो गए।

जिन नेताओं ने 75 साल पूरे कर लिए थे, उनमें लालकिण्या आडवाणी, मुरली मनोहर जाऊंझी जैसे नेता थे। उस समय एक मार्गदर्शक मंडल एवं भी बनाया गया था। तू तो उम्र में उनके अनुभवों को नेताओं को दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या यह नियम आगे भी जारी रहता है या केवल वही तक था। अगर यह नियम जारी रहता है, तो 17 सितंबर 2025 को पीएम मार्डी 75 साल के होने जा रहे हैं। जाहिर है, अगले लोकसभा में वह प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। हालांकि यह केवल कथन ही है, क्योंकि जैसकि हमने पहले ही कहा कि यह पार्टी को फैंड आखिरकारिक नियम नहीं है या पार्टी हितों को व्यापार में रखने के लिए सीमाएं लागू की गई हैं, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में यह नियम कड़वा से लागू किया गया और भाजपा के कई कदावर नेता संविधानिक पदों की जिम्मेदारी से बाहर हो गए।

जागरूकता अभियान, वैकल्पिक परिवहन समाधान और स्क्रीनिंग सुविधाओं की कमी ने इसकी जल्दी जारी की एवं साल साबित किया।

साथ ही, तकनीकी बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता ने इसकी विफलता को और उत्तराधिकार के लिए वैकल्पिक आवास आवंटन कर दिया है और आवश्यक मरम्मत के बाद ठेकेदार ने उसे 30 जून तक सौंपें कर वायदा

के मार्गदर्शक मंडल में अपना मामला है कि उसका आगामी पीएम कोन होगा।

वर्तमान आवास में ही निवास जारी रखने की अवधि आगे बढ़ाने से बांगला से विशेष वैकल्पिक आवास आवंटन के लिए वैकल्पिक आवास के प्रयोग वायदा की जगह दी थी। अब सवाल यह है कि क्या यह नियम आगे भी जारी रहता है या केवल वही तक था। अगर यह नियम जारी रहता है, तो 17 सितंबर 2025 को पीएम मार्डी 75 साल के होने जा रहे हैं। जाहिर है, अगले लोकसभा में वह प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। हालांकि यह केवल कथन ही है, क्योंकि जैसकि हमने पहले ही कहा कि यह पार्टी को फैंड आखिरकारिक नियम नहीं है या पार्टी हितों को व्यापार में रखने के लिए सीमाएं लागू की गई हैं, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में यह नियम कड़वा से लागू किया गया और भाजपा के कई कदावर नेता संविधानिक पदों की जिम्मेदारी से बाहर हो गए।

जागरूकता अभियान, वैकल्पिक परिवहन समाधान और स्क्रीनिंग सुविधाओं की कमी ने इसकी विफलता को और उत्तराधिकार के लिए वैकल्पिक आवास आवंटन कर दिया है और आवश्यक मरम्मत के बाद ठेकेदार ने उसे 30 जून तक सौंपें कर वायदा

के मार्गदर्शक मंडल में अपना मामला है कि उसका आगामी पीएम कोन होगा।

वैकल्पिक आवास में ही निवास जारी रखने की अवधि आगे बढ़ाने से बांगला से विशेष वैकल्पिक आवास आवंटन के लिए वैकल्पिक आवास के प्रयोग वायदा की जगह दी थी। अब सवाल यह है कि क्या यह नियम आगे भी जारी रहता है या केवल वही तक था। अगर यह नियम जारी रहता है, तो 17 सितंबर 2025 को पीएम मार्डी 75 साल के होने जा रहे हैं। जाहिर है, अगले लोकसभा में वह प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। हालांकि यह केवल कथन ही है, क्योंकि जैसकि हमने पहले ही कहा कि यह पार्टी को फैंड आखिरकारिक नियम नहीं है या पार्टी हितों को व्यापार में रखने के लिए सीमाएं लागू की गई हैं, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में यह नियम कड़वा से लागू किया गया और भाजपा के कई कदावर नेता संविधानिक पदों की जिम्मेदारी से बाहर हो गए।

जागरूकता अभियान, वैकल्पिक परिवहन समाधान और स्क्रीनिंग सुविधाओं की कमी ने इसकी विफलता को और उत्तराधिकार के लिए वैकल्पिक आवास आवंटन कर दिया है और आवश्यक मरम्मत के बाद ठेकेदार ने उसे 30 जून तक सौंपें कर वायदा

के मार्गदर्शक मंडल में अपना मामला है कि उसका आगामी पीएम कोन होगा।

वैकल्पिक आवास में ही निवास जारी रखने की अवधि आगे बढ़ाने से बांगला से विशेष वैकल्पिक आवास आवंटन के लिए वैकल्पिक आवास के प्रयोग वायदा की जगह दी थी। अब सवाल यह है कि क्या यह नियम आगे भी जारी रहता है या केवल वही तक था। अगर यह नियम जारी रहता है, तो 17 सितंबर 2025 को पीएम मार्डी 75 साल के होने जा रहे हैं। जाहिर है, अगले लोकसभा में वह प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। हालांकि यह केवल कथन ही है, क्योंकि जैसकि हमने पहले ही कहा कि यह पार्टी को फैंड आखिरकारिक नियम नहीं है या पार्टी हितों को व्यापार में रखने के लिए सीमाएं लागू की गई हैं, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में यह नियम कड़वा से लागू किया गया और भाजपा के कई कदावर नेता संविधानिक पदों की जिम्मेदारी से बाहर हो गए।

जागरूकता अभियान, वैकल्पिक परिवहन समाधान और स्क्रीनिंग सुविधाओं की कमी ने इसकी विफलता को और उत्तराधिकार के लिए वैकल्पिक आवास आवंटन कर दिया है और आवश्यक मरम्मत के बाद ठेकेदार ने उसे 30 जून तक सौंपें कर वायदा

के मार्गदर्शक मंडल में अपना मामला है कि उसका आगामी पीएम कोन होगा।

वैकल्पिक आवास में ही निवास जारी रखने की अवधि आगे बढ़ाने से बांगला से विशेष वैकल्पिक आवास आवंटन के लिए वैकल्पिक आवास के प्रयोग वायदा की जगह दी थी। अब सवाल यह है कि क्या यह नियम आगे भी जारी रहता है या केवल वही तक था। अगर यह नियम जारी रहता है, तो 17 सितंबर 2025 को पीएम मार्डी 75 साल के होने जा रहे हैं। जाहिर है, अगले लोकसभा में वह प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। हालांकि यह केवल कथन ही है, क्योंकि जैसकि हमने पहले ही कहा कि यह पार्टी को फैंड आखिरकारिक नियम नहीं है या पार्टी हितों को व्यापार में रखने के लिए सीमाएं लागू की गई हैं, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में यह नियम कड़वा से लागू किया गया और भाजपा के कई कदावर नेता संविधानिक पदों की जिम्मेदारी से बाहर हो गए।

जागरूकता अभियान, वैकल्पिक परिवहन समाधान और स्क्रीनिंग सुविधाओं की कमी ने इसकी विफलता को और उत्तराधिकार के लिए वैकल्पिक आवास आवंटन कर दिया है

